भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 258

No. 350] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

[N.C.T.D. No. 258

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भृमि एवं भवन विभाग

[रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) शाखा]

आदेश

दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

सं. एफ. 12(143)2017/मू.व.भ./पीएलजी/पार्ट-1/4176.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1395(अ) दिनांक 2 मई, 2017, के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 43 की उपधारा (4) के प्रथम नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मूल्य वर्धित कर नयायाधिकरण को रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में भी उपरोक्त अध्यिनियम के अनुसार नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, राजीव शुक्ला, अतिरिक्त सचिव (भूमि एवं भवन विभाग)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

[REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) BRANCH]

ORDER

Delhi, the 28th July, 2017

No. F. 12(143)/2017/L&B/PLG/Pt.I/4176.—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (4) of section 43 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number S.O. 1395(E) dated the 2nd May, 2017, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate Value Added Tax Tribunal of Government of National Capital Territory of Delhi as the Appellate Tribunal in relation to National Capital Territory of Delhi for the purpose of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, RAJEEVA SHUKLA, Addl. Secy. (L&B)